P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 **SHRINKHALA :** VOL-II * ISSUE-VIII April-2015
E: ISSN NO.: 2349-980X

सशक्त कार्यदल (EAG) एवं गैर सशक्त कार्यदल (NEAG) राज्यों का जनांकिकी विश्लेषण

राहुल श्रीवास्तव
विभागाध्यक्ष,
अर्थशास्त्र विभाग,
सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज,
गोरखपुर

सारांश

भारत एक वि"ाल प्रजातांत्रिक दे"ा जहाँ 1 अरब 21 करोड़ से अधिक लोग विभिन्न प्रान्तों में निवास करते है 35 राज्यों/केन्द्रीय शासित प्रदे"ाों में निवास करने वाले इस वि"ाल राष्ट्र में जनांकिकी वि"लेषण द्वारा उनके आर्थिक, सामाजिक, परिस्थितियों का अध्ययन करता है। इस शोध पत्र में किया गया है जो यह द"ार्ाता है कि दे"ा की कुल जनसंख्या को दो भागों में आसानी से वर्गीकृत किया जा सकता है। राज्यों को स"ाक्त कार्यदल (EAG- Empowerd Action Group) जनसंख्या और गैर स"ाक्त कार्यदल (NEAG- Non Empowerd Action Group) जनसंख्या में बाट कर जनसंख्या की द"ाकीय वृद्धि, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या की द"ाकीय वृद्धि राज्यों के मध्य भेदात्मक लिंग अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या का नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन तथा साक्षरता दरों में वृद्धि से सम्बन्धित अध्ययन किया गया है

मुख्य शब्द : सशक्त कार्यदल, ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, साक्षरता दर

पस्तावना

अध्ययन हेतु आकडों का संकलन जनगणना 1991 से 2011 तक लिया गया है प्राप्त आकड़ों का अनुपातिक वि"लेषण किया गया है साथ ही साथ विभिन्न लेखों पत्र–पत्रिकाओं से प्राप्त सन्दर्भ का प्रयोग भी अध्ययन पद्धति में किया गया है।

अध्ययन का उद्दे"य सशक्त कार्यदल राज्यों तथा गैर स"ाक्त कार्य दल के मध्य जनांकिकी समस्याओं जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, श्रम शक्ति का ग्रामीण क्षेत्रो से वाह्य पलायन तथा औद्योगिकरण पर पड़ने वाले अत्यधिक दवाब की जानकारी प्राप्त करन है। जनांकिकी सामूहिक रुप से मानव जनसंख्या की वृद्धि, विकास तथा गति"ाीलता का अध्ययन करता है।[1] दे"ा की कुल जनसंख्या को स"ाक्त कार्यदल (EAG- Empowerd Action Group) जनसंख्या में आठ राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदे"ा, उत्तराखण्ड, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदे"ा, छत्तिसगढ़ और उड़ीसा की जनसंख्या का वि"लेषण किया जाता है इसके अतिरिक्त सगैर स"ाक्त कार्यदल (NEAG- Non Empowerd Action Group) जनसंख्या में उपरोक्त आठ राज्यों को छोड़ कर शेष भारत की जनसंख्या को शामिल किया जा जाता है। सन् 1951–2011 के मध्य ई0ए0जी0 राज्यों की कुल जनसंख्या का अं"ा भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 45 प्रति"ात के मध्य रहा है। जनांकिकी जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण, गठन व उनमें परिवर्तन के घटकों जो कि जन्म, मृत्यु, क्षेत्रीय प्रवास एवं सामाजिक गति"ाीलता के रुप में जाना जाता है।[2] कुछ जनांकिकी वि"लेषकों ने यह स्पष्ट किया की जनांकिकी वर्तमान समय की जनसंख्या के आकार संरचना तथा वितरण में ही नहो बल्कि समय–समय पर इन तथ्यों के परिवर्तन और परिवर्तन के कारणों से भी सम्बन्ध रखता हैं। स्वतंत्रता के प"ाचात जनसंख्या की द"ाकीय वृद्धि में हम यह तथ्य देखने को मिलता है कि उन्नीसवी शताब्दी में वृद्धि दर पूर्व के वर्षों की तुलना में संतोषजनक है किन्तु अभी भी गैर स"ाक्त कार्यदल राज्यों की तुलना में स"ाक्त कार्यदल राज्यों की जनसंख्या वद्धि तीव्र गति से बढ़ रही है जो जनता में जागरुकता में कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रचार एवं प्रसार न होना और साथ ही साथ केन्द्र एवं सम्बन्धित राज्यों सरकारों की उदासीनता का परीणाम है ग्रामोण एवं नगरीय जनसंख्या की द"ाकीय वृद्धि को पृथक–पृथक अध्ययन करने के प"ाचात यह तथ्य सामने आया है कि 1951 से 1975 के मध्य भारत, स"ाक्त कार्यदल एवं गैर स"ाक्त कार्यदल राज्यों में ग्रामीण जनंसख्या की वृद्धि दर में जादा अन्तर नही था किन्तु क्रमिक रुप से 1981 के बाद से स"ाक्त कार्यदल राज्यों में सापक्षिक रुप से जनसंख्या की द"ाकीय वृद्धि दर में गिरावट का संकेत मिले है यह इस बात का परिचायक है स"ाक्त कार्यदल राज्यों में ग्रामीण स्तर

पर स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रचुर आव”यकता, जागरुकता हेतु सरकारी एवं गैर सकारी तन्त्र का क्रियान्वयन आव”यक है।

1951 से 2011 के मध्य शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के द”ाकीय वृद्धि के आकड़े हमें इस बात का बोध कराते है कि 1971 तक स”ाक्त कार्यदल राज्यों, गैर स”ाक्त कार्यदल राज्यों और समग्र रुप से भारत में जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में समान अनुपात से बढ़ रही थी किन्तु 1971–2011 के मध्य स”ाक्त कार्यदल राज्यों में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि सापेक्षिक रुप से अधिक रही है इसमे भी वि”ाेष रुप से 1971 से 1981 के मध्य यह स्थिति ज्यादा भयावह हो गयी है किन्तु 2001 के बाद हमें पुनः प्रारम्भिक स्थिति देखने को मिली है इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि वैं”वीकरण के बाद स”ाक्त कार्यदल राज्यों से कार्य”ील जनसंख्या का पलायन लगातार होता रहा ह जिसे नियंत्रित करने के लिए रोजगार परक उद्योगों की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नितान्त आव”यकता है।

स”ाक्त कार्यदल राज्यों, गैर स”ाक्त कार्यदल राज्यों और भारत की लिंगानुपात का वि”लेषण करना भी आव”यक हो जाता है क्योंकि लिंगानुपात किसी वि”ाष्ट समय पर किसी दे”ा स्थान व जाति वि”ाेष के स्त्री एवं पुरुषों की संख्या के बीच अनुपात को प्रद”ार्त करता है।[5] लिंगानुपात यह इंगित करता है कि किसी प्रदे”ा अथवा दे”ा में ”ा”ाु स्त्री अनुपात कितना अच्छा है। स”ाक्त कार्यदल राज्यों में 1951 से 2011 के मध्य यह अनुपात भारत एवं गैर स”ाक्त कार्यदल राज्यों से सदैव ही कम रहा है जो इन आठ वि”ाष्ट राज्यों में कमजोर ”ा”ाु स्त्री अनुपात का परिणाम है। इसके इतर गैर स”ाक्त कार्यदल राज्यों में लिंगानुपात भारत के औसत लिंगानुपात से हमे”ाा अधिक रहा है जो इस बात का स्पष्टीकरण करता है कि गैर स”ाक्त कार्यदल राज्यों में गर्भवती महिलओं एवं नवजात ”ा”ाुओं के चिकित्सा सुविधाओं उनके पालन पोषण एवं भ्रूण हत्या के प्रति लोगों में पूर्ण जागरुकता है ऐसी ही परिस्थिति कायम करके हम स”ाक्त कार्यदल राज्यों में लिंगानुपात को संतुलित कर सकते है।

मानव संसाधन उत्पादन मात्र एक ऐसा संसाधन है जो अन्य उपलब्ध संसाधनों की सहायता से उत्पादन प्रक्रिया का संचालन करता है इसी को ध्यान में रखकर हम अनुकुलतम जनसंख्या द्वारा अधिकतम आय प्राप्त करना चाहते है।[6] वर्तमान में अधिकक्य आय अर्जन हेतु यह स्वाभाविक है कि कार्य”ील जनसंख्या का नगरीकरण हो क्योंकि कषि उससे सम्बद्ध क्षेत्रों की उत्पादकता क्रमिक रुप से घट रही है। जबतक ग्रामीण स्तर पर हम रोजगार का सृजन नही करेगे जनसंख्या का पलायन नगरीय क्षेत्र की ओर स्वाभाविक है श्रम शक्ति को उत्पादक एवं उसमें पूँजी संचयन की शक्ति उत्पन्न करने के लिए उसका ओद्योगिक क्षेत्रों की ओर स्थानान्तरण आव”यक है।[7] स”ाक्त कार्यदल राज्यों की जनाकिकी हमें इस बात का बोद्ध कराते है कि ऐसे राज्यों में नगरीय जनसंख्या की कमी है जिसके कारण कम उत्पादक भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है। विगत 65 वर्षों में इन आठ राज्यों के नगरीय जनसंख्या का अनुपात धीमी गति से बड़ा है सापेक्षतया गैर स”ाक्त कार्यदल राज्यों में नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिक पाया जाता है इन तथ्यों का सन्दर्भ लेते हुए हम यह कह सकते है कि अभी भी स”ाक्त कार्यदल राज्यों में कृषि पर लोगों की निर्भरता जाता है।

किसी भी दे”ा अथवा प्रान्त में साक्षरता का अनुपात यह द”ााता है कि प्राथमिक ”ाक्षण संस्थाओं का कितना प्रभावी ढंग से विस्तार हुआ है और साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालयों से बच्चों के पलायन को हम कितने नियंत्रित कर पाये है ऐसे परिस्थिति का अवलोकन जब हम मुख्यतया स”ाक्त कार्यदल राज्यों पर करते है क्योंकि गैर स”ाक्त कार्यदल राज्यों में साक्षरता का स्तर स्वभाविक रुप से पहले से अधिकार रहा है दे”ा की वर्तमान औसत साक्षरता दर 73.0 प्रति”ात से है विगत 10 वर्षो मे पूरे दे”ा साक्षरता प्रवृत्ति में जहाँ 36.16 प्रति”ात की वृद्धि हुई है वही बिहार, झारखण्ड और उत्तर प्रदे”ा में इस अवधि में साक्षरता की प्रवृत्ति में क्रम”ाः 68.77 प्रति”ात, 55.62 प्रति”ात, 51.08 प्रति”ात वृद्धि देखने को मिली है जो संतोषजनक है। राजस्थान और अन्य स”ाक्त कार्यदल राज्यों में साक्षरता की वृद्धि दर अभी भी आ”ाानुरुप नही है। अतः हमें शैक्षणिक गुणवक्ता में सुधार कर, बच्चों में ”ाक्षा के प्रति जागरुकता पैदा करकें, ”ाक्षा की लागत में कमी करके उससे समान बच्चों तक पहुचाने की जिम्मेदारी सभी को उठानी होगी।

निष्कर्ष

अध्ययन से प्राप्त परिणाम यह द”ााते है कि स”ाक्त कार्यदल राज्यों के ग्रामीण स्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रचुर आव”यकता है जिसके लिए सरकारी एवं गैर सकारी उपक्रमों का नियोजन होना चाहिए, रोजगार परक उद्योगो द्वारा ग्रामीण पलायन को रोका जा सकता है। गर्भवती महिलाओं, नवजात ”ा”ाुओं के प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का उन्नयन एवं ”ाक्षा की लागत में कमी करके हम वाछित परिणाम प्राप्त कर सकते है स”ाक्त कार्यदल राज्यों गैर स”ाक्त कार्यदल राज्यों राज्यों के रुप में परिणित करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनओं का पारद”ीी एवं भ्रष्टाचार मुक्त क्रियान्वयन होना चाहिए जिसमें समाज के सभी वर्गां, समुदाय और आम जनता में सरकारी एवं गैर सकारी सुविधाओं के प्रति स्वतंत्र चिंतन की क्षमता बलवती हो सकें।

सन्दर्भ

1. Benjamm B, Elements of Vital Statistics.
2. Phillp H. Hauser and O.D. Duncon : The study of Population.
3. Warren.S. Thompson and Lewis : Population Problume.
4. Census : 1951 to 2011
5. Heer. David : Problume of Population studies.
6. Dalton : Essay on the Application of a capital to labour.
7. Ragner Nukrsy : Theory of capital Accumalation.
8. Indian Economy surrvey. 1991 to 2011